

राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर किसानों को मिलेंगी बड़ी सौगातें

हमारी जनकल्याणकारी योजनाएं आमजन के सम्पूर्ण सशक्तिकरण की ओर महत्वपूर्ण कदम : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश के किसानों को कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति और लाभ हस्तांतरण के बारे में जरूरी दिशा-निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं सिर्फ योजनाएं नहीं, बल्कि आमजन के सम्पूर्ण सशक्तिकरण की ओर बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों से बराबर सम्पर्क रखते हुए विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं का लाभ और जानकारी जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में विकसित राजस्थान बनाने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अपनी प्रथम वर्षगांठ पर किसानों को बड़ी सौगातें देने की प्रभावी तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 5 हजार 500 फार्मपौण्ड के लिए किसानों के खातों में सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी है। इसी प्रकार 2 हजार किलोमीटर पाइपलाइन, 5 हजार किसानों को तारबंदी के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नहरी क्षेत्र में 500 डिगिंगों,



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोरा, शिखर अग्रवाल, कुलदीप रांका, श्रेया गुहा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

एक हजार किसानों को कृषि उपकरण सहायता और 2 हजार वर्मा कम्पोस्ट इकाइयों के लिए अनुदान सहायता प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत 3 हजार किसानों को गोवर्धन से जैविक खाद उत्पादन के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि नमो ड्रोन दीदी योजना में 50 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त भी किसानों को जारी की जाएगी। शर्मा ने कहा कि सरकार कुसुम योजना के माध्यम से सोलर पम्प की स्थापना के लिए 15 हजार किसानों को

लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ड्रिप इरिगेशन ही सिंचाई हेतु एक दीर्घकालिक समाधान है। सरकार द्वारा 15 हजार किसानों को ड्रिप इरिगेशन के लिए वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इसके साथ ही 1 हजार लाभार्थियों को कृषि एवं अकृषि ऋण ब्याज अनुदान प्रदान किए जाएंगे।

इस अवसर पर पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड वितरण के साथ-साथ एक हजार नए डेयरी बूथों का आवंटन, 200 नए बल्क मिलक कूलर्स की स्थापना और एक हजार नए दूध संकलन केंद्रों का उद्घाटन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार

ने मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि देते हुए 183.22 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

इस दौरान मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कुलदीप रांका, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रेया गुहा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश के पूर्ण विकास के लिए भाजपा ही जरूरी : भजनलाल

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सात विधानसभा क्षेत्रों में उप चुनाव पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वे दिन की शुरुआत उप चुनाव की तैयारियों के लिए बूथ, मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर तक के सैकड़ों पदाधिकारियों से फोन पर बातचीत करके करते हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर उप चुनाव की तैयारियों का फीडबैक लिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान कहा कि विधानसभा उप चुनाव में कांग्रेस के जातिवाद के एग्जेंड पर हमारी सरकार का विकास का एजेंडा भारी है। उन्होंने कहा कि दस महीने के छोटे समय में हमने रिकॉर्ड काम किए हैं जिससे कांग्रेस की नींव हिल चुकी है और जनता का हमारी सरकार पर विश्वास जमा है। जिन मुद्दों पर कांग्रेस वर्षों तक राजनीति करती

- मुख्यमंत्री लगातार ले रहे पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चुनावी फीडबैक
- उप चुनाव में कांग्रेस के जातिवाद पर भारी भाजपा का विकास का एजेंडा
- 'कांग्रेस राज में घोटालेबाजों और माफियाओं ने मचा रखी थी लूट'

रही, हमारी डबल इंजन सरकार उनसे संबंधित समझौते कर तेजी से उन्हें धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान से पहले ही हमारी सरकार ने 18 लाख करोड़ के निवेश एमओयू किए हैं और इन एमओयू को धरातल पर लाने के लिए सरकार पूरी तरह समर्पित होकर कार्य कर रही है, ये निवेश राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। पेपर लोक जैसे

मामलों में एसआईटी ने 190 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस राज में किस कदर माफियाओं और घोटालेबाजों ने लूट मचा रखी थी। उन्होंने कहा कि हम दिखावे के बिना निरंतर जन कल्याण के कार्य करते हैं, जबकि कांग्रेस काम का नाम करने में भी बेईमानी करती है। उप चुनाव में कांग्रेस के बागी ही अपने प्रत्याशियों को निपटाएंगे।

कालवाड़ महाविद्यालय में बड़ी प्रवेश तिथि

जयपुर। कैबिनेट मंत्री झोटवाड़ा के विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के अध्यक्ष प्रयासों और समर्पण से युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। कालवाड़ महाविद्यालय में प्रवेश की तिथियों को बढ़ा दिया गया है, जिससे अब भी इच्छुक छात्र दाखिला ले सकते हैं। यह कदम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें शिक्षा के नए अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार युवाओं की शिक्षा और विकास के लिए समर्पित है। यह महाविद्यालय झोटवाड़ा क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कर्नल राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और विजन से राजस्थान की भाजपा सरकार सुनिश्चित कर रही है कि क्षेत्र के हर युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।

परीक्षा स्थगित

जयपुर। जगदुरु रामानंदचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय ने शिक्षा शास्त्री के प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की सात नवंबर से चौदह नवंबर तक चलने वाली परीक्षा में आंशिक संशोधन किया है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. शंभु कुमार झा ने बताया कि प्रयोग के 42 केंद्रों पर दो पारियों में होने वाली परीक्षा में 13 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव के चलते स्थगित किया गया है। झा ने बताया कि अब यह परीक्षा संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पूर्व निर्धारित समय और परीक्षा केंद्र पर 16 नवंबर को होगी। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार इंटीग्रेटेड शास्त्री-शिक्षा शास्त्री की 13 नवंबर को होने वाली परीक्षा 23 नवंबर को होगी।

जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए 658.12 करोड़ रुपए स्वीकृत

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अध्यक्ष प्रयासों एवं पहल पर प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए 23 जिलों के 46 पंचायत समितियों के 507 गांवों में 181 कार्यादेश जारी करने के लिए 658.12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे न केवल प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों को गति मिलेगी बल्कि इन जिलों के 1.12 लाख घरों में घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध करवा कर लाभान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार सरकार ने इस योजना को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से निर्धारित समय अवधि में काम पूरे नहीं हो सके। अब राज्य सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। योजना को गति देने के लिए 658.12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

जलदाय मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि प्रदेश के अजमेर, बालोतरा, बारां, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, डीग, धौलपुर, गंगापुरसिटी, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, केरकड़ी, पाली, सवाईमधोपुर, सिरोही, श्री गंगानगर एवं उदयपुर के 33 पंचायत समितियों के 413 गांवों के लिए 520.28 करोड़ रुपये की 137 कार्यादेश जारी किये जायेंगे। इन स्वीकृतियों से न केवल जल जीवन मिशन के कार्यों को गति मिलेगी बल्कि इन जिलों के गांवों में रहने वाले व्यक्तियों को योजना के तहत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा जो कि हर घर जल के सपने को साकार करेगा।

भाजपा में परिवार भाव के साथ एकजुटता से किया जा रहा है कार्य : श्रवण सिंह बगडी

जयपुर। भाजपा प्रदेश के उपचुनावों को लेकर पूर्णरूप से सक्रिय नजर आ रही है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जहां हर उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर चुनावी रणनीति तय कर रहे हैं, वहीं भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में विकास के नाम पर आमजन से मतदान की अपील भी कर रहे हैं। इधर दूसरी ओर भाजपा पदाधिकारी, कैबिनेट के मंत्री सरकार के कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। संगठन स्तर पर भाजपा का एक-एक पदाधिकारी, कार्यकर्ता चुनावों में जुटा हुआ है। भाजपा प्रदेश कार्यलय से महामंत्री श्रवण सिंह बगडी और उनकी टीम लगातार उपचुनावों में प्रवास कार्यक्रमों के साथ क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय जननेताओं को आमजन के बीच भेज रहे हैं। भाजपा प्रदेश कार्यलय पर नियमित रूप से

केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित 17 मंत्री, विधायक और भाजपा पदाधिकारी 6 नवम्बर को रहेंगे प्रवास पर

चुनाव प्रबंधन के साथ प्रवास कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि भाजपा सभी सातों सीटों पर भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज कराएंगी। भाजपा में कार्यकर्ता से लेकर आमजन एकजुट होकर कमल के लिए कार्य कर रहे हैं। भाजपा में एकजुटता नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस में भितरघात देखने को मिल रहा है। भाजपा सरकार के खंजीपण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 10 माह में किए ऐतिहासिक कार्यों को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं, फिर चाहे वो बजट घोषणाएं हो या फिर

जोतेंगे। श्रवण सिंह बगडी ने बताया कि बुधवार 6 नवंबर को खीवर विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, राज्य सरकार के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल प्रवास पर रहेंगे। इसी तरह रामगढ़ में उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, गुजरात योग बोर्ड के चैयरमैन शीशापाल, विधायक भागवंत टांकडा, बुधुंनूं में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनियां, सांसद राजेंद्र गहलोल, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती और सैनिक कल्याण बोर्ड अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर, दीसा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, देसद उपअध्यक्ष प्रभुलाल सैनी, सलुंबर में मंत्री जोराराम कुमावर, विधायक सुरेंद्र सिंह, दीपति माहेश्वरी, समाराम गारासिया तथा चौरासी में मंत्री बाबूलाल खराडी प्रवास पर रहेंगे।

मिस फ्रांसिस का देहांत



जयपुर। सेंट जेवियर स्कूल की वरिष्ठतम पूर्व टीचर मिस एम.फ्रांसिस का मंगलवार को देहांत हो गया। वे संतोकाब दुर्लभजी अस्पताल जयपुर के अवेदना आश्रम में रहती थीं। उनकी अंतिम यात्रा बुधवार को तीन बजे अवेदना आश्रम से रवाना होगी और घाटगेट स्थित चर्च पर साढ़े तीन बजे पहुंचेगी।

खाते से पैसे निकाले

जयपुर। मालवीय नगर थाना इलाके में बैंक कर्मचारी बनकर युवक को फोन कर किसी की राशि जमा करने के नाम पर एटीएम की जानकारी लेकर उसके खाते से 75 हजार रुपए निकाल लिए।

जिंदा भ्रूण को मृत बताकर प्री-मैच्योर डिलीवरी की

एम.एम.एस. मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व कंट्रोलर और जनाना अस्पताल के अधीक्षक पर 5.20 लाख रुपए का हर्जाना

जयपुर। जयपुर महानगर प्रथम की स्थाई लोक अदालत ने गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु बताकर प्री-मैच्योर डिलीवरी करने और बाद में शिशु की मौत को गंभीर लापरवाही माना है। इसके साथ ही अदालत ने विपक्षी एमएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व कंट्रोलर और जनाना अस्पताल के अधीक्षक पर 5.20 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है। अदालत ने कहा कि विपक्षी हर्जाना राशि का भुगतान परिवार को तीस दिन में करे। लोक अदालत के अध्यक्ष मनोज कुमार सहारिया व सदस्य सीमा शर्दुल ने यह आदेश बीना मीना के प्रार्थना पत्र पर दिए। प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता विजी अग्रवाल ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान प्रार्थिया ने जनाना अस्पताल को देखरेख में इलाज शुरू करवाया। उसकी एक नवंबर 2023 को अल्ट्रा

■ अदालत ने इस मामले में शिशु की मौत को अस्पताल की गंभीर लापरवाही माना है

सोनोग्राफी की, जिसमें 25 सप्ताह के भ्रूण की मृत्यु होना बताया। जबकि प्रार्थिया ने कहा कि उसे गर्भ में भ्रूण की हरकत महसूस हो रही है, लेकिन डॉक्टर ने उसे कहा कि तत्काल भ्रूण नहीं निकाला तो संक्रमण होने से उसकी जान जा सकती है। इसके बाद 9 नवंबर 2023 को इंजेक्शन देकर उसकी प्री मैच्योर डिलीवरी करवाई गई। इसमें उसने जीवित शिशु को जन्म दिया और उसे बच्चा वार्ड में भेजना बताया। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि डिलीवरी के करीब

तीन घंटे बाद उसे बताया कि प्री मैच्योर डिलीवरी के चलते शिशु की मृत्यु हो गई है। इस पर अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर क्षतिपूर्ति राशि देने की गुहार की। इसके जवाब में अस्पताल प्रशासन की ओर से कहा गया कि मरीजों की भीड़ और अधिक कार्य होने के कारण सोनोग्राफी बदलने से इनकार नहीं किया जा सकता। यूनिट के डॉक्टर ने सोनोग्राफी पर ही प्रसव का निर्णय लिया था। शिशु को बचाने का हर संभव प्रयास भी किया गया था और उसे पहले एनआईसीयू में भर्ती करने के बाद वेंटीलेटर पर भी रखा गया, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे में उनकी ओर से लापरवाही नहीं बरती गई है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अस्पताल पर हर्जाना लगाया है।

महेश जोशी की मुश्किलें बढ़ेंगी, ए.सी.बी. ने मुकदमा दर्ज किया

जे.जे.एम. घोटाले में जोशी सहित 20 आरोपियों के नाम

■ इसी मामले में ई.डी. भी कर रही है जांच, जोशी के नजदीकी संजय बड़ाया और फर्म प्रोप्राइटर की हो चुकी है गिरफ्तारी

जयपुर, (का.प्र.) कांग्रेस सरकार में पीएचडी मंत्री रहे महेश जोशी पर ईडी के बाद राजस्थान ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भी जल जीवन मिशन में घोटाले में जोशी सहित 20 लोग और दो फर्मों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। इनमें पीएचडी के अधिकारियों, पीएचडी के ठेकेदार और निजी व्यक्तियों के नाम भी शामिल हैं। एसीबी के डीजी डॉ. रविप्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विनानगर की रिपोर्ट के आधार पर जल जीवन मिशन में गड़बड़ियों के संबंध में 20 लोगों और दो फर्मों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसकी जांच एसीबी की विशेष शाखा के एसपी पुर्णेन्द्र सिंह को सौंपी गई है। एसीबी में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पूर्व मंत्री महेश

पदमचंद जैन, फर्म श्रीश्याम टच्युबुवेल कंपनी, शाहपुरा, इरकोन इंटरनेशनल के ऑफिस सहायक मुकेश पाठक, जोशी के नजदीकी संजय बड़ाया, किशन गुप्ता, तपन गुप्ता, नमन खंडेलवाल सहित अन्य के खिलाफ जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।

इससे पहले जल जीवन मिशन घोटाले में अवैध रूप से धन के लेन-देन को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने भी केस दर्ज किया था। ईडी ने इस मामले में पदमचंद जैन, महेश मित्तल, पीयूष जैन सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार

कर पूछताछ भी की थी। इसी मामले में सीबीआई ने भी पीएचडी के अधिकारियों व अन्य के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। अब एसीबी ने महेश जोशी सहित 20 लोगों और दो फर्मों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है।

यह मामला एसीबी ने खोला था। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले एसीबी ने जल जीवन मिशन के बिल पास करने की एवज में रिश्वत का लेन-देन करते ठेकेदार और पीएचडी के अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि कई जगहों पर बिना पाइप लाइन बिछाए ही भूतान कर दिया गया। इसके साथ ही हरियाणा पर की गई पाइप बिछाने की बात भी सामने आई थी। अब एसीबी आरोपियों को कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है।

पर्याप्त मानव संसाधन नहीं रखने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई की सिफारिश

सरकारी योजनाओं से भी असम्बद्ध होंगे

जयपुर। राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को कहा है कि संग्रुणा प्रदेश में अधिमान चलाकर सभी अस्पतालों की जांच की जाए और वर्ष 2010 के प्रावधानों के तहत उचित मानव संसाधन नहीं रखने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। आयोग ने कहा कि संसाधनों की अनुपलब्धता के बावजूद मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले अस्पतालों को चिरंजीवी योजना सहित अन्य सभी सरकारी योजनाओं से भी डी-लिस्ट किया जाए। आयोग ने भवानीमंडी के निजी अस्पताल में बच्चे की मौत के मामले में उसके पिता को पांच लाख रुपए की मुआवजा राशि देने को कहा है। अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह इसमें से ढाई लाख रुपए की राशि दोषी अस्पताल नवजीवन

हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के प्रबंधन या दोषी चिकित्सकों से वसूल कर सकती है। आयोग सदस्य जस्टिस आरसी झाला ने यह आदेश आशीष पारेता के परिवार पर दिए आयोग ने कहा कि दोषी अस्पताल की शिशु रोग इकाई को बंद करने, अस्पताल प्रबंधन पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाने और चिरंजीवी योजना से डी-लिस्ट करने मात्र से परिवार को आठ साल के बेटे की मौत से हुई क्षति को पूर्णतः संभव नहीं है।

परिवाद में बताया गया कि 25 जनवरी, 2023 को उसके आठ साल के बेटे प्रहल पारेता के पेट दर्द होने पर उसे नवजीवन अस्पताल, भवानीमंडी लेकर गए अस्पताल में पूछने पर पता चला कि यहां बच्चों के डॉक्टर शैलेन्द्र पाटीदार हैं। वहीं वहां मौजूद दूसरे चिकित्सक कुलदीप सिंह ने इलाज

करना शुरू कर दिया। दो घंटे बाद कुलदीप सिंह के स्थान पर डॉ. हरिवल्लभ ने आकर इलाज किया और डॉ. शैलेन्द्र पाटीदार का थोड़ी देर में आना बताया। इसके बाद दोपहर में हरिवल्लभ ने बताया कि डॉ. पाटीदार के शादी में जाने के कारण वे अस्पताल नहीं आ सकते हैं। इस पर वे बच्चे को गंभीर हालत में दूसरे अस्पताल ले गए। इस दौरान रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। परिवार में बताया गया कि हरिवल्लभ एमबीबीएस चिकित्सक ही नहीं है। ऐसे में अयोग्य चिकित्सक के इलाज के कारण बच्चे की मौत हुई है। मामला आयोग में आने के बाद राज्य सरकार की ओर से अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई कर उसकी जानकारी आयोग को दी गई। इस पर आयोग ने राज्य सरकार को सभी अस्पतालों के संबंध में विस्तृत सिफारिशें की हैं।

शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 12 साल पहले शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर 16 बिंदुओं पर दिए निर्देशों की पालना को लेकर राज्य सरकार से 11 नवंबर तक जवाब पेश करने को कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता विमल चौधरी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने 21 मई 2012 को राज्य सरकार को 16 बिंदुओं पर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए थे। इसके तहत हर वार्ड में सौ सफाई कर्मचारी लगाने, सप्ताह के हर दिन सफाई करने, सिंगल टियर सिस्टम से सफाई, कचरा पात्र लगाने, डोर टू डोर कचरा संग्रहण और चार मोबाइल मजिस्ट्रेट सहित अन्य निर्देश दिए थे। इसके साथ ही अदालत ने इन निर्देशों की पालना को लेकर हर तीन माह में रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

समृद्ध विरासत और परम्पराओं का प्रदेश है राजस्थान : देवनानी

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी चार देशों की यात्रा के दौरान मंगलवार को सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) पहुंचे। देवनानी का सिडनी पहुंचने पर अधिकारियों ने स्वागत किया। देवनानी ने सिडनी में आयोजित भारत रीजन के 67वें राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ के सम्मेलन की डेलीगेट ब्रीफिंग में भाग लिया। देवनानी ने सम्मेलन में मौजूद उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, कर्नाटक,



■ विधान सभा अध्यक्ष देवनानी पहुंचे सिडनी

तमिलनाडु सहित भारत के विभिन्न प्रदेशों के विधान सभा अध्यक्षण और सांसदगण से मुलाकात की। इस मौके पर देवनानी ने कहा कि राजस्थान प्रदेश की अपनी समृद्ध विरासत, परम्पराओं और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विशिष्ट पहचान है। जयपुर के महल, उदयपुर की झीले और जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर के भव्य दुर्ग देशी तथा विदेशी सैलानियों के लिए पसंदीदा स्थान हैं। राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के लिए प्रति दिन हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं।

देवनानी इस अध्ययन यात्रा के दौरान विभिन्न देशों के विधायी निकायों का अवलोकन करने के साथ संसदीय प्रतिनिधिगण से लोकातांत्रिक मूल्यों के सुदृढीकरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करेगी। उल्लेखनीय है

कि प्रति वर्ष आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के अध्यक्ष एक मंच पर एकत्रित होकर लोकातांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न विषयों पर संवाद करते हैं। इस बार का राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ

का सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में 5 से 8 नवम्बर तक हो रहा है। संसदीय संघ का यह 67वां सम्मेलन है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए अध्यक्ष देवनानी के साथ विधान सभा के विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा भी गये हैं।